RNI No. UPHIN/2000/03766 ISSN No. 2581-3528 ₹ : 20

केशव संवाद

(दिसम्बर 2024)

विकसित भारत - 2047
हरित ऊर्जा से प्रगति का पथ

हिन्दी पंचांग दिसम्बर-2024

मार्गशीर्ष दिसम्बर-2024 पौष

रवि SUN	सोम MON	मंगल TUE	बुध WED	गुरु THU	शुक्र FRI	शनि SAT
1 अमावस्या Amawasya	2 प्रतिपदा Pratipada	3 द्वितीया Dwitiya	4 तृतीया Tritiya	5 गणेश चतुर्थी व्र. CHATURTHI	6 राम जानकी विवाह Sita Ram Vivah	7 षष्ठी Shasthi
8 सप्तमी / अष्टमी Saptami	9 नवमी Navami	10 दशमी Dashami	11 गीता ज. मोक्षदा एकादशी Geeta Jayanti Mokshda Ekadashi	12 द्वादशी Dwadashi	13 प्रदोष व्र. PRADOSH	14 चतुर्दशी/पूर्णिमा Chaturdashi/Full Moon
15 संक्रांति / Sankranti पूर्णिमा / Full Moon Dattatrey Jayanti	16 प्रतिपदा Pratipada	17 द्वितीया Dwitiya	18 तृतीया Tritiya	19 चतुर्थी Chaturthi	20 पंचमी Panchami	21 षष्ठी Shashthi
22 सप्तमी Saptami	23 अष्टमी Astami	24 नवमी Navami	25 दशमी Dashami CHRISTMAS	26 सफला एकादशी EKADASHI	27 द्वादशी Dwadashi	28 त्रियोदशी TRIYODASHI
29 चतुर्दशी Chaturdashi	30 सोमवती अमावस्या Somavati Amawasya	31 प्रतिपदा Pratipada			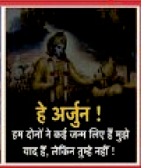 	

दिसम्बर -2024 (व्रत-त्यौहार)

- **01** रविवार — अन्वाधान, मार्गशीर्ष अमावस्या
- **02** सोमवार — इष्टि
- **03** मंगलवार — चन्द्र दर्शन
- **06** शुक्रवार — विवाह पञ्चमी
- **07** शनिवार — चम्पा षष्ठी
- **08** रविवार — भानु सप्तमी
- **11** बुधवार — गीता जयन्ती, मोक्षदा एकादशी
- **13** शुक्रवार — प्रदोष व्रत
- **14** शनिवार — दत्तात्रेय जयन्ती
- **15** रविवार — धनु संक्रान्ति, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अन्वाधान
- **16** सोमवार — इष्टि
- **18** बुधवार — अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
- **22** रविवार — भानु सप्तमी
- **26** बृहस्पतिवार — सफला एकादशी
- **28** शनिवार — प्रदोष व्रत
- **30** सोमवार — सोमवती अमावस, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, पौष अमावस्या
- **31** मंगलवार — इष्टि

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/03766

ISSN No. 2581-3528

दिसम्बर, 2024

वर्ष : 24 अंक : 12

प्रबंध निदेशक
अणंज कुमार त्यागी

संपादक
कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक
डॉ. नीलम कुमारी

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201309
फोन न. 0120 4565851
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक रमन चावला द्वारा चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा.लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105 आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

पर्यावरण योद्धा पीटर और नीनो कौर -सतीश शर्मा....................05

विकसित भारत 2047 : हरित ऊर्जा के माध्यम ... - अमन दुबे........................06

बेटी की पाठशाला - डॉ. दीपा रानी...................08

स्वस्थ समाज के निर्माण का दर्पण है वात्सल्य तत्व - डॉ. दीपा रानी..................10

आत्मनिर्भरता का पर्याय बनता हुआ अमरोहा ... - डॉ. शिवा शर्मा................12

प्लास्टिक प्रदूषण : भारत के लिए बनता संकट - भावना भारद्वाज................14

बांग्लादेश में कट्टरपंथी - प्रो. सुनील दत्त त्यागी.........16

पर्यावरण जागरुकता के साथ ही समाज सेवा की अलख जगा रहे राजीव...............17

डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण - प्रहलाद सबनानी................18

लखपति दीदी ग्रामीण सशक्तीकरण की उभरती लहर - डॉ. परमवीर केसरी...........20

मोहम्मद यूनुस और डीप स्टेट द्वारा बांग्लादेश में ... - पंकज जगन्नाथ जयस्वाल....21

जन्मदिवस विशेष - सुब्रह्मण्य भारती -डेस्क..............................23

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया,'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय...

परम वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्...

राष्ट्र के परम वैभव लक्ष्य के लिए संकल्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारा अपनी स्थापना काल से ही माँ भारती को उच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रवाहमान हैं। संघ की यह लंबी यात्रा हजारों स्वयंसेवको के त्याग, तप व बलिदान का परिणाम है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के वैश्विक संकट यथा जातिगत हिंसा, पर्यावरण असंतुलन, युद्ध, विस्तारवाद और आतंकवाद मानव सभ्यता को लील जाने को खड़े हैं। मानवाधिकारों की हत्या और आतंकवाद का मिला जुला रूप वर्तमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीडन और मजहबी नरसंहार में भी दिखाई दे रहा है। समस्याओं से ग्रस्त संपूर्ण विश्व शान्ति एवं सौहार्द के लिए भारत की ओर देख रहा है। भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम्' एवं 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की भावना से पोषित सत्य सनातन संस्कृति में सभी देशों की आस्था एवं विश्वास है। संपूर्ण विश्व आज भारत की संस्कृति के अनुकूल वैश्विक परिवर्तन चाहता है इसके लिये पहले भारत को समर्थ होना होगा। यही कारण है कि संघ के माननीय संघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने भारत को समृद्ध, समर्थ एवं सशक्त बनाने के लिए पंच परिवर्तन पर बल दिया है।

ये पंच परिवर्तन है - स्व, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण और नागरिक कर्तव्य। यही पंच परिवर्तन भारत को वैभव संपन्न राष्ट्र के रूप में विकसित कर विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर एवं भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग खाकर सामाजिक समरसता का उत्कर्ष उदाहरण प्रस्तुत किया, आज भी भारत में ऐसे आदर्शों पर चलने वाला समाज है जो चरैवेति-चरैवेति मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। एक सुसंस्कृत एवं चरित्रवान व्यक्ति से ही सुसंस्कृत समाज एवं समुन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः सत्य ही है कि समाज का कर्तव्यनिष्ठ, आत्मनिर्भर, प्रकृति प्रेमी, परिवार प्रेमी, समाज सेवी व्यक्ति ही अपने आचरण से सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है

संघ साधना की अभिव्यक्ति आचरण से करते हम ।
समरस हो समाज तो होगा अपना देश सबल।।
कर्तव्यनिष्ठ हो राष्ट्र तो होगा अपना देश सुदृढ़।
आत्मनिर्भर हो समाज तो होगा अपना देश प्रबल।।
प्रकृति प्रेमी हो जन-जन तो होगा अपना देश निर्मल।
कुटुंबमयी स्वरुप हो समाज तो होगा अपना देश सबल ।।

अतः सभी सुधि पाठकों से विनम्र निवेदन है कि संघ के शताब्दी वर्ष में पंच अमृत धाराओं के साथ एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

पर्यावरण योद्धा पीटर और नीनो कौर

सतीश शर्मा
संघचालक, केशव भाग, नोएडा महानगर

नीनो को रक्त कैंसर का पता चला था और कीमोथेरेपी के बाद उनके फेफड़े दिल्ली की प्रदूषित हवा से निपटने में संघर्ष कर रहे थे। एक डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने उन्हें जैविक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने गोवा में कुछ समय बिताया और फिर दिल्ली लौटकर अपने घर को एक स्वास्थ्यपूर्ण और आत्मनिर्भर स्थान में बदलने का संकल्प लिया। आज, यह घर हरित जीवनशैली का एक बेहतरीन उदाहरण बन चुका है, जो प्राचीन तकनीकों और आधुनिक पर्यावरणीय उपायों का संयोजन है। यह घर दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में एक मरु बगीचे के रूप में खड़ा है, जहां स्वच्छ हवा, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और जैविक खेती के जरिए एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इस अनोखे घर का निर्माण पीटर और नीनो के व्यक्तिगत संघर्ष व साहस का प्रतीक है। दिल्ली वालों के लिए एक उद्धरण है की मानव अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है।

पीटर और नीनो के घर की सबसे खास बात यह है कि इस घर में 15 हजार पौधे लगाए गए हैं, जो हवा को शुद्ध और प्रदूषण रहित बनाते हैं। यही वजह है कि इस घर को पेड़-पौधे वाला छोटा उपवन भी कहते है। इसी कारण से इस घर की हवा एकदम साफ, शुद्ध और स्वास्थ्य के अनकूल रहती है।

गंभीर प्रदूषण और धुंध के कारण से जहां दिल्ली में साँस लेना मुश्किल है, वहां एक ऐसा घर होना जो न केवल मानव जीवन के अनकूल है व घर के सदस्यों को प्रदूषण से बचाए रखता है, बल्कि 15,000 पौधों और आत्मनिर्भर तकनीकों के जरिए 10-15 का अद्भुत वायु गुणवत्ता सूचकांक को कायम रखता है। उनका घर दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में स्थित है, जहां पीटर सिंह और नीनो कौर ने अपने घर को पर्यावरणीय अनकुल बनाया। जो दिल्ली में एक उद्धरण बन गया है।

पीटर सिंह और नीनो कौर ने अपने घर का निर्माण पारंपरिक तरीकों का पालन कर बनाया है, जिसमें ईंटों को सीमेंट के बजाय चूने के गारे से जोड़ कर दीवार चुनीं गई है। घर में दीवारों पर आधुनिक पेंट की जगह पुराने समय के अनुसार चूने का उपयोग किया गया है, जो न केवल घर के अंदर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है वहीं पर्यावरण को भी जीवन अनुकूल बनाता है। छत पत्थर की टुकड़ों से बनाई गई है, इस कारण घर मोसमानुकूल रहता है।

इस घर में पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, उनका घर किसी भी बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भर नहीं है। सौर पैनलों के जरिए यह घर अपनी सारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। इस घर में जल संरक्षण के लिए 15,000 लीटर के टैंक का इस्तेमाल वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। बारिश के पानी को बहने से रोककर उसका भविष्य में इस्तेमाल किया जाता है। इस पानी का इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है, जैसे कि सिंचाई, धुलाई, पीने का पानी, बागवानी।

सब्जियों व पानी के मामले में पीटर सिंह का यह घर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। : दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में यह घर न केवल हवा में सुधार करता है, बल्कि यहां के निवासी अपना भोजन भी खुद उगाते हैं। पीटर और नीनो अपने घर में जैविक तरीके से सब्जियां उगाते हैं, जिससे उन्हें बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वे साल भर जैविक और सतत् (सस्टेनेबल) खेती के तरीके अपनाते हैं। दिल्ली में पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, लेकिन पीटर और नीनो ने पराली को एक संसाधन के रूप में उपयोग करने का तरीका खोज निकाला है। वे पराली को जैविक खाद के साथ मिलाकर घर में मशरूम उगाने के लिए खाद तैयार करते हैं, जिससे न केवल पराली का सही उपयोग होता है, बल्कि यह घर के भोजन के उत्पादन में भी मदद करता है।

इनके घर में मछली पालन और मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीक का उपयोग किया गया है। उनके घर में चार तलाबों में मछलियां पाली जाती हैं और साथ में बिना मिट्टी के पेड़-पौधे उगाए जा रहे हैं। फिश टैंक के पानी में अमोनिया होता है। यह पानी पौधों तक पहुंचाया जाता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया उस पानी के अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, पौधों को पानी का न्यूट्रिशन मिल जाता है और बदले में, वे पानी को प्यूरिफाई कर देते हैं और फिर से यही पानी मछलियों के टैंक में चला जाता है, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इस तरह पानी की भी काफी बचत होती है और मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। इस तरह हर दिन सिर्फ 1,000 लीटर पानी का ही इस्तेमाल होता है। गंभीर प्रदूषण और धुंध के कारण से जहां दिल्ली मे साँस लेना मुश्किल है वहीं पीटर सिंह और नीनो कौर के द्वारा किया गया उपरोक्त कार्य आज हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ■

ISSN No. 2581-3528

विकसित भारत 2047 : हरित ऊर्जा के माध्यम से प्रगति का पथ

अमन दुबे
शोध छात्र, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली

हरित ऊर्जा पर्यावरण संतुलन दृष्टि का मूल आधार है, जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसकी ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। यह मांग 2023 तक भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बना चुकी है।

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से प्रस्तुत किया, वह महज एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण है। यह लक्ष्य भारत को न केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रयास है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। हरित ऊर्जा इस दृष्टि का मूल आधार है, जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसकी ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। यह मांग 2023 तक भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बना चुकी है। बावजूद इसके, ऊर्जा की बड़ी मात्रा आज भी जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त की जाती है। 2023 तक भारत अपनी 60 प्रतिशत ऊर्जा मांग कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से पूरी कर रहा था। कोयला और पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता न केवल आयात पर भार डालती है, बल्कि इससे पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं भी गंभीर होती जा रही हैं। इन चुनौतियों का समाधान हरित ऊर्जा के जरिए ही संभव है।

भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है। 2023 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के पार पहुंच गई, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा का समावेश है। इनमें से सौर ऊर्जा में भारत ने वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और यह पांचवें स्थान पर है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जो इसके कुल ऊर्जा मिश्रण का 50 प्रतिशत होगी। यह लक्ष्य न केवल घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक जलवायु नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करेगा। भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' को भी एक मील का पत्थर माना जा सकता है। 2023 में शुरू हुए इस मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हाइड्रोजन उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक होगा। इसके साथ ही, यह मिशन 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने में भी योगदान देगा। यह पहल न केवल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक मजबूत योगदान देगी।

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को वैश्विक सहयोग और प्रतिबद्धताओं से भी बल

ISSN No. 2581-3528

मिला है। 2015 में भारत द्वारा शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ISA के तहत, 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' परियोजना का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का नेटवर्क बनाना है। इस गठबंधन में 110 से अधिक देश शामिल हैं, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, वित्त और शोध को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। 2021 के COP26 सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धताओं को और सुदृढ़ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत नामक योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, भारत ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए +100 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हरित ऊर्जा का प्रसार केवल पर्यावरणीय फायदे तक सीमित नहीं है। यह भारत की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से देश में लाखों नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने तकनीकी और उच्च-कुशल नौकरियों का सृजन किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, 2030 तक हरित ऊर्जा क्षेत्र में 10 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इससे न केवल कृषि उत्पादन लागत में कमी आ रही है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ रही है। हरित ऊर्जा के उपयोग से न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि यह पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करता है। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग वायु गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कम होता है और जनता का जीवन स्तर बेहतर होता है। इसके अलावा, हरित ऊर्जा का उपयोग जल संसाधनों को संरक्षित करने में भी सहायक है। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं के विपरीत, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में जल की खपत नगण्य होती है। यह पहल भारत के जल संकट को हल करने में भी उपयोगी है।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय ऊर्जा तंत्र की दृष्टि हर भारतीय का सपना है, और इसे साकार करने के लिए हर नागरिक का योगदान आवश्यक है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब यह हरित ऊर्जा आधारित विकास यात्रा एक नए युग की शुरुआत करेगी, जो भारत को न केवल विकसित राष्ट्र बल्कि विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगी।

हरित ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति के बावजूद, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता बड़ी चुनौती है। भारत ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापक नीतियां लागू की हैं, लेकिन इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। बिजली ग्रिड का आधुनिकीकरण एक अन्य चुनौती है। नवीकरणीय ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में शामिल करने के लिए तकनीकी और संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। भूमि अधिग्रहण, जो सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवश्यक है, कभी-कभी सामाजिक असंतोष का कारण बनता है। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करने और उचित मुआवजा देने की नीतियां अपनाई हैं। जनसामान्य को हरित ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूक करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हरित ऊर्जा को अपनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार और उद्योग दोनों की जिम्मेदारी है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित ऊर्जा का प्रसार एक अनिवार्य शर्त है। भारत ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत 2030 तक 80 प्रतिशत तिपहिया और दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। साथ ही, हरित ऊर्जा गलियारों (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स) का विकास नवीकरणीय ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में एकीकृत करने में मदद करेगा। ये गलियारे ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों को दिशा देगा। यह दृष्टिकोण न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। भारत का यह प्रयास केवल घरेलू ऊर्जा संकट का समाधान नहीं है, बल्कि यह वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करता है।

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयास 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार करने के लिए निर्णायक साबित होंगे। यह केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ी छलांग है। हरित ऊर्जा न केवल भारत को पर्यावरणीय चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाएगी, बल्कि इसे एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित यह दृष्टि हर भारतीय का सपना है और इसे साकार करने के लिए हर नागरिक का योगदान आवश्यक है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब यह हरित ऊर्जा आधारित विकास यात्रा एक नए युग की शुरुआत करेगी, जो भारत को न केवल विकसित राष्ट्र बल्कि विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगी। ■

ISSN No. 2581-3528

'बेटी की पाठशाला' महिलाओं को बना रही सशक्त और स्वावलंबी

डॉ. दीपा रानी

सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र व समाज को सशक्त बनाने की एक मजबूत नींव है। जिसके तहत ही स्वस्थ समाज का निर्माण सम्भव है। विश्व पटल पर जिस किसी भी देश ने सामाजिक समरसता का अनुपालन किया है आज वह सुख समृद्धि से ओत–प्रोत है तथा विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। भारतवर्ष की सनातनी सांस्कृतिक परम्परा में समरसता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत ने विश्व स्तर पर अखण्डता में एकता संजोकर अपनी एक अद्भुत पहचान बनायी है। यहाँ हर राज्य की सभ्यता, पहनावा, रहन–सहन, बोली भाषा भिन्न–भिन्न है। इस देश में 122 विभिन्न भाषाएँ तथा 1599 उपभाषायें बोली जाती हैं। फिर भी यह देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ एक अद्भुत राष्ट्र है। इसे षड्यंत्रकारी आक्रांताओं ने कई बार विखंडित करने का प्रयास किया लेकिन यह देश हर बार उठ खड़ा हुआ।

भारतवर्ष की सनातनी सांस्कृतिक परम्परा में समरसता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत ने विश्व स्तर पर अखण्डता में एकता संजोकर अपनी एक अद्भुत पहचान बनायी है। यहाँ हर राज्य की सभ्यता, पहनावा, रहन-सहन, बोली भाषा भिन्न-भिन्न है। इस देश में 122 विभिन्न भाषाएँ तथा 1599 उपभाषायें बोली जाती हैं।

पिछले कई दशकों से विश्व स्तर पर अशान्ति देखने को मिल रही है। कई देश आतंक और युद्ध के दंश की चपेट में हैं। समाज में अस्थिरता का वातावरण बहुत तेजी से फैला है। तकनीकी होड़ में जीवन के उपयोगी मूल्यों का दोहन हो रहा है। जीवन जीने के लिए उपयोगी हवा, पानी आदि की गुणवत्ता का मानक स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आज आतंक, युद्ध तथा सामाजिक विखण्डता का प्रभाव भारतवर्ष में भी दिखने लगा है। जिस वजह से देश की समरसता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा दिखाई दे रहा है। देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक अशान्ति गम्भीर समस्या बनकर उभर रही है जो की आर्थिक व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सरकारें भिन्न–भिन्न योजनाओं की मदद से देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक भेदभाव तथा धार्मिक उन्माद के उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं। भारत के कई शुभचिन्तक, विचारक, लेखक, सामाजिक शिल्पकार अलग–अलग माध्यमों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कुछ कर्मवीर अपने निजी प्रयासों से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक पहल अनुज भाटी जी की है जो कि खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सड़कों के किनारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए निःशुल्क पाठशाला चला रहे हैं। वह गरीब बेसहारा बेटियों को शिक्षित तथा सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क किताब, कॉपी, पेन के साथ भोजन की भी व्यवस्था कराते हैं। इनकी पाठशाला आईआईटी दिल्ली की सड़कों के पास, दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर के पास, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास तथा लाजपत नगर के

ISSN No. 2581-3528

फ्लाइओवर के पास लगती हैं। 2016 में इन्होंने अपने प्रयास को एक एनजीओ का रूप दिया जहाँ लगभग 200 से भी अधिक बच्चे शिक्षा, गीत – संगीत, खेलकूद तथा नाना प्रकार की प्रगतिशील गतिविधियों में शामिल होकर सशक्त व स्वावलंबी बन रहे हैं। अनुज भाटी जी के सकारात्मक प्रयास से आज कई घरों की बेटियाँ आत्मनिर्भर होकर समाज में अपना योगदान भी दे रही हैं।

अनुज भाटी जी गढ़गंगा गाँव चकनवाला अमरोहा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पिता एक किसान हैं तथा उनका निजी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा स्वयं के खर्चे पर मजदूरी कर पूर्ण की। वर्ष 2012 में दिल्ली में आकर उन्होंने कर्ज लेकर एमबीए की डिग्री पूरी की और कुछ वर्षों तक बैंकिंग सेक्टर में कार्य भी किया। गरीबी के संघर्ष के दौरान उन्होंने कई ऐसी घटनाएँ देखी जहाँ बेटियों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं ने उनको झकझोर दिया। वह एक वाक्या तो अपने ही घर का ही बताते हैं जहाँ उनके पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए अस्सी हजार रुपये कर्ज लेने पड़े और कहतें हुए उनका गला रुँध जाता है कि उनके पिता ने वह कर्ज बहुत मुश्किल से चुकाया। कई वर्षों तक वह संघ से जुड़े रहे और वहीं से उन्होंने सेवा भाव का गुण सीखा। देश और समाज के लिए संघ कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव को देख कर उनमें समाज की कुरीतियों से लड़ने की हिम्मत जागी और इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने बेटियों को सड़को के किनारे निःशुल्क शिक्षा देना शुरु कर दिया। अपने रोज के काम से समय निकालकर गरीब बेसहारा बेटियों को स्वावलंबी बनाने के जुनून ने भाटी जी को पूर्ण रूप से समाज सेवा के भाव से ओत–प्रोत कर दिया और वह अपनी नौकरी छोड़ कर अपना पूरा समय समाज सेवा में देने लगे। आज दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में उनकी 30–30 सदस्यों की कई टोली बनी हुई है जिसमे हर टोली के 6 से 7 लोग बिना किसी लाभ के सक्रियता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में वे कई शैक्षिक संस्थानों से जुड़ कर बेटियों तथा महिलाओं को उनके दायित्व व अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बेटी रक्षक एक संगठन भी बनाया हुआ है जिसमें अभी तक लगभग 25000 से भी अधिक स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। अब तक वह लगभग 50 से अधिक बालिका विद्यालयों का दौरा कर चुके हैं। बेटी रक्षक संगठन के तहत वह हर स्कूल में बेटियों व अन्य लोगों को शपथ दिलाने का कार्य भी करते हैं कि "न अपराध करेंगे न ही अपराध होने देंगे" वह इन सभी स्कूलों में बेटियों को सरकार द्वारा दी गई योजनाओं और उनकी सुरक्षा में किए जाने वाले रक्षा संबंधी कार्यों की जानकारियों से भी अवगत कराते हैं ताकि महिलायें तथा बेटियाँ उसका सही उपयोग कर सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह आईआईएमसी के साथ मिलकर कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी क्रम में वह हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज के लिए योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने का भी काम करते हैं। अनुज भाटी जी का मानना है कि हर बच्चे को शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है तथा देश में शैक्षिक तथा लैंगिक भेद को पूर्णरूप से समाप्त करना अति आवश्यक है, इसलिए अपने नागरिक कर्तव्य का अनुपालन करते हुए वह गरीब बेसहरा बच्चियों को शिक्षा का उपहार देने का पूर्ण प्रयास कर रहे है।

बेटी की पाठशाला नाम से पंजीकृत यह एनजीओ बेटियों की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड का भी वितरण करती है। साथ ही यह बेटियों को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से कन्या पूजन जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा इनका एनजीओ उपयुक्त वर तलाश कर बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाती हैं।

बेटी की पाठशाला नाम से पंजीकृत यह एनजीओ बेटियों की स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड का भी वितरण करती है। साथ ही यह बेटियों को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से कन्या पूजन जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा इनका एनजीओ उपयुक्त वर तलाश कर बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाता हैं। यह एनजीओ गरीब बच्चों की आवश्यकता अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से खुले स्थान पर अपनी पाठशाला चलाती है जिसकी वजह से अधिक से अधिक गरीब बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं। साथ ही मदद करने वाले लोग भी इन तक सुगमता से पहुँच कर अपना योगदान दे पा रहे हैं। इस एनजीओ के साथ अपनी स्वेच्छा से काम करने वाले स्वयंसेवक अपने निजी कार्यक्रम से समय निकालकर इस संस्थान को अपना योगदान दे रहे हैं। इन सभी प्रयासों का मूल उद्देश्य देश में एकता, भाईचारा और सदभाव कायम कर लोगों में समरसता का भाव पैदा करना तथा भारत को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करना एवं देश की बेटियों को सफलता की उचाईयों तक पहुँचाना है। ■

ISSN No. 2581-3528

स्वस्थ समाज के निर्माण का दर्पण है

वात्सल्य तत्व

यदि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्यों को समझ जाएँगे और उस पर अमल करेंगे तभी एक स्वस्थ समाज और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान कर पायेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि वह हमारे नागरिक होने के अधिकार और कर्तव्यों को संतुलित करता है।

नागरिक कर्तव्य का अनुपालन ही सशक्त समाज एवं विकासशील राष्ट्र के निर्माण की कुंजी हैं। यदि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्यों को समझ जाएँगे और उस पर अमल करेंगे तभी एक स्वस्थ समाज और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान कर पायेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि वह हमारे नागरिक होने के अधिकार और कर्तव्यों को संतुलित करता है। पुरातनकाल से ही हमारे देश में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है। हमे हमेशा ही अपने नागरिक होने के साथ–साथ अपने दायित्वों को निभाने पर जोर दिया जाता रहा है। हमारे धर्म ग्रंथ चाहे वह रामायण हो या भगवद्गीता, लोगों को कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित करती हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमे अधिकार माँगने की आवश्यकता नहीं होगी। सनातन की इस अवधारणा का निर्वहन करते हुए एवं अपने पिता के पद चिह्नों पर चलते हुए श्रीमान प्रणव विभांशु जी ने गरीब व बेसहारा बच्चों के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई और उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के प्रयास से निःशुल्क वात्सल्य तत्व केंद्र की शुरुआत की। वात्सल्य तत्व का यह नाम भारत माता की प्रार्थना गीत से लिया गया है। जिसके तहत इस संस्था से जुड़ने वाले हर स्वयंसेवक अपनी वात्सल्यमयी भावना के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। गाजियाबाद में स्थिति यह केन्द्र सेवा भाव से जुड़े स्वयंसेवकों की मदद से उनकी क्षमतानुसार गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। युवाओं की इस टोली में एमएनसी प्रोफेशनल्स तथा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। राजनगर के गढी गाँव में वात्सल्य तत्व निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी स्थित हैं। इस टोली के हर सदस्य सप्ताह में दो दिन वात्सल्य दिवस मनाते हैं जिसके तहत आठवीं तक के बच्चों के लिए वह निःशुल्क ट्यूशन की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा इस संस्थान से जुड़े स्वयंसेवी झुग्गी झोपड़ी के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए आये दिन नये–नये तरीकों से देश और समाज में हो रहे बदलावों से भी अवगत कराते रहते हैं। इस केंद्र का थीम है 'वी डोंट नीड योर मनी बट नीड योर टाइम' अर्थात् अपने किसी भी स्वयंसेवकों से यह पैसे नहीं बल्कि उनके समय की अपेक्षा रखते हैं इनका मानना है कि बेसहारा बच्चों को अधिक से अधिक भावनात्मक तथा नैतिक सहयोग की आवश्यकता होती है। शिक्षा की इस मुहिम में प्राची तथा कणिका का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस एनजीओ का मूल उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को आपराधिक गतिविधियों से बचा कर उन्हें शिक्षित तथा जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। सन् 2018 में वात्सल्य तत्व ने अपने स्वयंसेवकों के अथक सेवा भाव से समाज में एक अलग पहचान बनायी। यह केंद्र ट्रेनिंग की मदद से अपने स्वयंसेवकों को सामाजिक कार्यों के प्रति दायित्व निर्वहन करने का प्रशिक्षण देता है तथा उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियाँ देता है। अब तक इस केंद्र से 400 से भी अधिक लोग

जुड़ चुके हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान इन स्वयंसेवकों ने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण काम किये। वात्सल्य तत्व के वालंटियर्स द्वारा किये गए कुछ कार्य जो समाज के द्वारा सराहे गए।

इन्स्पायर चेंज : जब कोरोना महामारी के दौरान घर–घर में बीमारी की वजह से अवसाद का माहौल बना हुआ था। तब इस केंद्र के स्वयंसेवक विवेक, मानसी शर्मा, आयुषी और अर्नव ने ऑनलाइन माध्यम से इन्स्पायर चेंज नामक मुहिम की शुरुआत की जिसके तहत डिप्रेशन के शिकार लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये। इन्होंने डिजिटल माध्यम के जरिये ऐसे लोगों के घर तक पहुँचने का प्रयास किया जिन्हें महामारी के चपेट में अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा, साथ ही उन तक हर प्रकार का सहयोग पहुँचने का भी प्रयास किया।

वोकल फॉर लोकल : वंचित परिवारों को चयनित करना, उनके लिए सुलभ रोजगार खोजना, फिर रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के माध्यम से उनसे उत्पादन करवाना और फिर उनको मार्केट से जोड़कर तैयार वस्तुओं को बेचने की कला सिखाना।

इस मुहिम के तहत इस संस्थान से जुड़े स्वयंसेवक कुणाल, कणिका और धर्मेंद्र ने गरीबों को रंगीन दिए बनाना सिखाया। इंजीनियरिंग, सीए और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे युवाओं ने करोना में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को दिया रंगना और उसे बेचना सिखाया और उन परिवारों के दिये के काम को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट भी किया ।

जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों का वितरण : वात्सल्य तत्व संस्थान से जुड़े रॉबिन पाल और विवेक शर्मा ने न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया अपितु अपनी टोली की मदद से गरीबों को कपड़ों की व्यवस्था करने के लिए क्लॉथ डोनेशन मुहिम भी चलाया। ये स्वयंसेवक गाजियाबाद की सोसाइटीज में जाकर कम्बल व गरम कपड़े इकट्ठा कर झुग्गियों में रह रहे गरीबों तक इन गरम कपड़ों को पहुँचाते हैं।

वात्सल्य तत्व संस्थान ने नागरिक कर्तव्य का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है जो न केवल युवाओं को अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सफल हुआ है बल्कि उन्हें गरीब व बेसहारा लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मदारियों का बोध भी करवा रहा है।

युवा इंग्लिश : इस मुहिम के तहत वात्सल्य तत्व से जुड़े आयुशी और हर्षिता ने गरीब युवाओं को नौकरी और रोजगार में मदद पहुँचाने के उद्देश्य से युवा इंग्लिश नामक मुहिम की शुरुआत की। इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इंग्लिश की निःशुल्क कोचिंग देकर गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। इस संस्थान के इन अद्भुत प्रयासों की वजह से कई गरीबों को रोजगार मिलने में आसानी हुई तथा वे सरलता से अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने में कामयाब हुए।

पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था : यह संस्थान पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी करता है। कोविड महामारी के दौरान जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब इस संस्थान के स्वयंसेवक अर्णव, शिवांगी, कनिक, मानसी पोखरियाल, एवं अन्य लोग प्रतिदिन रात की रोटी, हरी सब्जी एवं अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर दर्जनों वालंटियर्स साथ रोजाना प्रातः 5 बजे से पशुओं को खाना खिलाने का काम करते थे।

वालंटियर ट्रेनिंग : ऐसे अनेक सेवा कार्यों के साथ वात्सल्य तत्व समाज में कार्यकुशल स्वयंसेवकों के शिक्षण व निर्माण में कार्यरत है। यहाँ से कार्य का अनुभव प्राप्त कर कई स्वयंसेवक अब अपनी अलग संस्था बनाकर समाज निर्माण में उत्तम योगदान दे रहे हैं, किसी नई संस्था का निर्माण करने और उसके संचालन में भी वात्सल्य तत्व परिवार का सहयोग ऐसे स्वयंसेवकों को मिलता रहता है।

वात्सल्य तत्व संस्थान ने नागरिक कर्तव्य का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है जो न केवल युवाओं को अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सफल हुआ है बल्कि उन्हें गरीब व बेसहारा लोगों के प्रति उनका सामाजिक जिम्मदारियों का बोध भी करवा रहा है। आज कई स्वयंसेवक वात्सल्य तत्व से जुड़ कर समाज के प्रति अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं।

वात्सल्य तत्व निरंतर इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार से वंचित युवाओं को निःशुल्क प्रोफेशनल स्किल सिखाकर उन्हें उत्तम रोजगार का अवसर दिलाना भी है। ■

आत्मनिर्भरता का पर्याय बनता अमरोहा जिले का गांव मोहरका

डॉ. शिवा शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेजी विभाग)
झम्मन लाल पी. जी. कॉलेज हसनपुर जिला, अमरोहा

मोहरका गांव में बिना सरकारी मदद के यहां की महिलाओं ने अपराध के लिए बदनाम गांव को अपने हुनर के दम पर नई पहचान दिलाई है। गांव में प्रवेश करते ही हर आंगन व चबूतरे पर महिलाएं साड़ी पर लगने वाली मोती की लेस बनाती दिखती हैं। गांव की मस्जिद में कारोबारी आते हैं, वहीं से महिलाओं को आर्डर दिए जाते हैं। 10 साल पहले जहां तीन-चार घरों में काम शुरू हुआ था, अब करीब पांच सौ से अधिक घरों में यह काम किया जा रहा है।

अमरोहा भारतीय गणराज्य के प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला और शहर है और इस जिले का मुख्यालय भी यहीं है। यह मुरादाबाद मंडल का हिस्सा है। इस जिले का क्षेत्रफल 2,249 वर्ग किलोमीटर है। अमरोहा जिले में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, धनौरा (सुरक्षित), नौगांवां सादत, अमरोहा और हसनपुर शामिल हैं।

अमरोहा, जिसे पहले ज्योतिबा फुले नगर कहा जाता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल 1997 को इसका नाम बदलकर अमरोहा रख दिया साथ ही इसे जिला घोषित कर दिया। मोहरका पट्टी ग्राम पंचायत, अमरोहा जिला परिषद के गजरौला पंचायत समिति भाग में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। मोहरका पट्टी ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 2 गाँव हैं। मोहरका पट्टी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित एक गांव है। यह जिले का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला गांव है और क्षेत्रफल के हिसाब से जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है।

यूपी का अनोखा गांव जहां मस्जिद से होता है रोजगार का एलान, महिलाएं

बन रहीं आत्मनिर्भर : अमरोहा जनपद में गांव मोहरका पट्टी को बेटियों ने अपने हुनर से रोजगार वाला गांव बना दिया है। दिल्ली से कारोबारी गांव में आते हैं और मस्जिद में संपर्क करते हैं। वहां से काम के लिए एलान होता है, बेटियां आती हैं और आर्डर ले जाती हैं। 10 साल पहले तीन–चार घरों में शुरू हुआ काम अब 500 घरों तक फैला हुआ है।

प्रशिक्षण के बिना ही पीढ़ी दर पीढ़ी हुनर बढ़ रहा है। घर–घर नारी सशक्तीकरण का नारा बुलंद हो रहा है।

इस गांव में बिना सरकारी मदद के यहां की महिलाओं ने अपराध के लिए बदनाम गांव को अपने हुनर के दम पर नई पहचान दिलाई है। गांव में प्रवेश करते ही हर आंगन व चबूतरे पर महिलाएं साड़ी पर लगने वाली मोती की लेस बनाती दिखती हैं। गांव की मस्जिद में दिल्ली के कारोबारी आते हैं, वहीं से महिलाओं को आर्डर दिए जाते हैं। 10 साल पहले तीन–चार घरों में काम शुरू हुआ था, अब करीब पांच सौ से अधिक घरों में काम किया जा रहा है।

अब महिलाओं का हुनर ही यहां की पहचान है। गांव के अधिकांश घरों में महिलाएं लेस तैयार करने का काम करती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 10 साल पहले दो–तीन महिलाओं ने किसी तरह सीखकर लेस बनाने का काम शुरू किया। उन्हें देखकर अन्य महिलाओं में भी रोजगार को लेकर जागरूकता आई।

पुरुष खेती करते हैं और घर पर महिलाएं लेस से आय करती हैं। इसे पट्टी में जड़ी झालर भी कहा जाता है। महिलाओं के मुताबिक लेस की सप्लाई दिल्ली व गाजियाबाद के लिए की जाती हैं। उन्हें आर्डर के साथ लेस का रॉ मैटेरियल भी दिया जाता है। आर्डर भी सभी महिलाओं को बराबर–बराबर दिए जाते हैं। कारोबारी पिछले आर्डर का तैयार माल ले जाते हैं।

एक झालर के सौ रुपये: महिलाओं के मुताबिक एक झालर तैयार करने के सौ रुपये

मिलते हैं। दिनभर में एक घर की महिलाएं पांच–छह लेस तैयार कर लेती है। उन्हें पांच–छह सौ रुपये मिल जाते हैं। यानी एक परिवार को 15–20 हजार रुपये तक आय हो जाती है। महिलाएं घर का काम भी करती हैं और खाली वक्त में लेस तैयार करती हैं। महिलाओं के काम में परिवार के पुरुष भी पूरा सहयोग करते हैं। अधिकांश परिवार मुस्लिम होने के बाद भी किसी को महिलाओं के काम करने पर आपत्ति नहीं है। गांव में महिलाओं द्वारा मोतियों से जुड़ा हुआ काम किया जाता है।

> **दिनभर में एक घर की महिलाएं पांच-छह लेस तैयार कर लेती है। उन्हें पांच-छह सौ रुपये मिल जाते हैं। यानी एक परिवार को 15-20 हजार रुपये तक आय हो जाती है। महिलाएं घर का काम भी करती हैं, और खाली वक्त में लेस तैयार करती हैं। महिलाओं के काम में परिवार के पुरुष भी पूरा सहयोग करते हैं। अधिकांश परिवार मुस्लिम होने के बाद भी किसी को महिलाओं के काम करने पर आपत्ति नहीं है।**

गांव की परवीन बताती हैं कि इस कारोबार से सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हैं। शादियों के सीजन में यह कारोबार अच्छा चलता है। नजमा का कहना है कि पांच–छह साल से इस कारोबार को कर रही हूं। परिवार का खर्चा ठीक चल रहा है। गांव की महिलाओं को देखकर ही मोतियों की लेस बनाने का तरीका सीखा था। अब आजीविका चलाने के काम आ रहा है।

लेस के बारे में जानिए: लेस सादा कपड़े की 10 मीटर की पट्टी पर तैयार होती है। इसमें चमकीले धागों के साथ मोती लगाए जाते हैं। व्यापारी लेस ले जाकर पॉलिस्टर की साड़ी पर लगवाते हैं। दिल्ली व गाजियाबाद में यह काम काफी होता है। व्यापारी भी एक लेस को ढाई सौ रुपये तक में साड़ी तैयार कराने वालों को बेच देते हैं। ■

ISSN No. 2581-3528

प्लास्टिक प्रदूषण : भारत के लिए बनता संकट

भावना भारद्वाज
शोध छात्रा, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली

प्लास्टिक प्रदूषण वर्तमान में दुनिया की सबसे विकट पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। भारत में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, जहां सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और अनुचित निपटान ने इसे एक गंभीर संकट बना दिया है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और आर्थिक संसाधनों पर भी व्यापक प्रभाव डाल रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां संसाधनों और जागरूकता की कमी है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत में प्लास्टिक का उपयोग और उसका निपटान बड़े पैमाने पर हो रहा है। चिंता का विषय यह है कि इस प्लास्टिक कचरे का केवल 60 प्रतिशत पुनर्चक्रण किया जा रहा है, जबकि शेष 40 प्रतिशत लैंडफिल, जलाशयों और खुले वातावरण में फेंक दिया जाता है। यह कचरा धीरे-धीरे मिट्टी, जल स्रोतों और वायुमंडल को दूषित करता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से आता है। इसमें प्लास्टिक की

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लास्टिक उत्पादों का अंधाधुंध उपयोग। सस्ता, हल्का, और आसानी से उपलब्ध होने के कारण प्लास्टिक वस्तुएं उपभोक्ताओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक की थैलियों और पैकेजिंग का उपयोग व्यापक है,

बोतलें, बैग, स्ट्रॉ, फूड पैकेजिंग और अन्य उत्पाद शामिल हैं, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिए जाते हैं। जुलाई 2022 में भारत सरकार ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया, लेकिन इसका क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लास्टिक उत्पादों का अंधाधुंध उपयोग। सस्ता, हल्का, और आसानी से उपलब्ध होने के कारण प्लास्टिक वस्तुएं उपभोक्ताओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक की थैलियों और पैकेजिंग का उपयोग व्यापक है, लेकिन इन्हें पुनर्चक्रित करने की व्यवस्था बेहद असंगठित है। इसके अलावा, भारत में औद्योगिक उत्पादन में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है। प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बढ़ा है, लेकिन इनके उचित निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। एक अन्य कारण प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में तकनीकी और वित्तीय बाधाएं हैं। भारत में अधिकांश नगरपालिकाएं प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से वंचित हैं। साथ ही, नागरिकों के बीच जागरूकता की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है।

प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव बहुआयामी है। यह पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैव विविधता और आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। प्लास्टिक का क्षरण धीमी गति से होता है और यह सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बना रह सकता है। प्लास्टिक कचरा जलाशयों और नदियों में जमा होकर उन्हें दूषित करता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान

(NEERI) के अनुसार, भारत में गंगा, यमुना, और अन्य प्रमुख नदियां प्लास्टिक कचरे के जमाव से बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। समुद्रों में प्लास्टिक का जमाव भी एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय समुद्री नीति (2021) की रिपोर्ट बताती है कि भारत के समुद्रों में हर साल लगभग 0.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जमा होता है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है और मछलियों, कछुओं और मूंगे की चट्टानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन भोजन और पानी में मिलकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पाया है कि प्लास्टिक कचरे से उत्पन्न सूक्ष्म कण (Microplastics) कैंसर, हृदय रोग और हार्मोनल असंतुलन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, प्लास्टिक जलाने से निकलने वाले गैसें श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। कृषि भूमि पर प्लास्टिक कचरे की उपस्थिति मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है। यह फसलों की पैदावार को प्रभावित करता है और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यटन स्थलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य न केवल प्लास्टिक कचरे को कम करना है, बल्कि इसके प्रभावी पुनर्चक्रण और निपटान को भी सुनिश्चित करना है। 1 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने सिंगल–यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए गए हैं। ये नियम उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को उनके कचरे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। Extended Producer Responsibility (EPR) के तहत उत्पादकों को उनके प्लास्टिक उत्पादों के कचरे के निपटान और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में प्लास्टिक कचरे को हटाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग सिंगल–यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को बंद कर सकें।

प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में प्रत्येक भारतीय का योगदान आवश्यक है। यदि हम सभी सामूहिक रूप से सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें, और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाएं, तो हम न केवल पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्थायी भारत की नींव भी रख सकते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें सरकार, उद्योग और आम जनता की सहभागिता महत्वपूर्ण है। सिंगल–यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करना और इसके विकल्पों को बढ़ावा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल उत्पाद, जैसे कपड़े के थैले और कागज के बैग, प्लास्टिक के प्रभावी विकल्प बन सकते हैं। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी नवाचार आवश्यक हैं। वेस्ट–टू–एनर्जी और प्लास्टिक–टू– फ्यूल जैसी परियोजनाएं प्रभावी साबित हो सकती हैं। उद्योगों को हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर प्लास्टिक प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। मीडिया और गैर–सरकारी संगठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण भारत और पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, लेकिन इनका सफल कार्यान्वयन सभी हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर करता है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में प्रत्येक भारतीय का योगदान आवश्यक है। यदि हम सभी सामूहिक रूप से सिंगल–यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाएं, तो हम न केवल पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्थायी भारत की नींव भी रख सकते हैं। ■

ISSN No. 2581-3528

बांग्लादेश में कट्टरपंथी

प्रोफेसर (डॉ.) सुनील दत्त त्यागी
किसान पी.जी. कॉलेज, सिंभावली (हापुड़)

बांग्लादेश में दो महीने पहले वॉयस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में कट्टरपंथी यूनुस ने जिस 'रीसेट' का जिक्र किया था, वह भ्रष्टाचार से गिरी संस्थाओं की पवित्रता को बहाल करने तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन उनके शासन का समर्थन करने वाले अन्य लोगों के विचार स्पष्ट रूप से दूसरे हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो बांग्लादेश के इस्लामवादी गढ़ बनने की पूरी आशंका है, जिसके पूर्वी भारत के लिए भयावह परिणाम होंगे। इस्लामवादियों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है। चूंकि हिंदू समुदाय, मोटे तौर पर अवामी लीग का समर्थक था इसलिए 5 अगस्त के बाद राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप का सबसे बुरा असर उन पर ही पड़ा। हालांकि, हिंदुओं के राजनीतिक नेतृत्व के उत्पीड़न के साथ–साथ 1.3 करोड़ हिंदू आबादी में असुरक्षा पैदा करने का एक टारगेटेड कदम भी उठाया गया। बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचारों पर ध्यान देना तत्काल आवश्यक है। हिंसक हमले, हत्याएं, लूटपाट, आगजनी और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति और मंदिरों को निशाना बनाना एक गंभीर मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इन घटनाओं के बीच, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियां इस संकट का समाधान करने के बजाय मूक दर्शक बनी हुई हैं। आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं द्वारा उठाई गई आवाज को अन्याय और उत्पीडन का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में बांग्लादेशी सरकार द्वारा इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी और कारावास न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। हमारी मांग है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों के समर्थन से हिंदू समाज का दमन रोका जाए। यह निराशाजनक है कि वैश्विक संगठनों ने अभी तक उस स्तर की चिंता नहीं दिखाई है जो इस गंभीर स्थिति के लिए जरूरी है। भारत सरकार ने इस मामले पर बेहद सावधानी और संयम दिखाया है। एक संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देना उचित नहीं है, लेकिन विश्व समुदाय की ओर से किसी प्रभावी कार्रवाई के बिना एक बड़े हिंदू समुदाय का उत्पीड़न देखना अस्वीकार्य है। यह जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर ठोस और समर्पित कदम उठायें। अतीत में, हिंदुओं के उत्पीड़न के कारण, समुदाय के सदस्यों ने हमेशा खुद को दूर कर लिया है और कानूनी या अवैध तरीकों से भारत में प्रवेश करने का सहारा लिया है।

आजादी के समय पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 23 प्रतिशत थी, लेकिन 2022 तक यह घटकर सिर्फ 8 प्रतिशत ही रह गई। यह इस्लामिक राज्य में रहने का परिणाम है। इन मुद्दों को तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ संबोधित करने का समय आ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि दुनिया इस पर ध्यान दे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और जीवन की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। ■

ISSN No. 2581-3528

पर्यावरण जागरुकता के साथ ही समाजसेवा की अलख जगा रहे राजीव

आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण संबंधी बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। मानव ने अपनी गतिविधियों के द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी पृथ्वी देंगे जहां जीवन की संभावना न के बराबर होगी। पर्यावरण के प्रति कर्तव्य निर्वहन प्रत्येक मानव के लिए धर्म है। अनेक लोग पर्यावरण संकट को देखकर अपने इस धर्म को पहचान चुके हैं और निरंतर अपने प्रयासों के द्वारा अपने आस–पास के समाज को जागरुक कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं गाजियाबाद में रहने वाले डॉ. राजीव त्यागी 'राज' जो पिछले अनेक वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित हैं। वे छोटी–छोटी गतिविधियों के द्वारा अपने इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ऐसे ही प्रयासों के द्वारा वे अब तक लाखों पौधे लगा चुके हैं। अपने परिवार में जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या अन्य किसी भी खुशी के अवसर पर वह विशाल पौधारोपण करते हैं।

मौसम को ध्यान में रखकर जुलाई से लेकर अक्टूबर माह तक वे छायादार और फलदार पौधों का रोपण करते हैं। उनके द्वारा लगाए गए पौधों में पीपल, नीम, बेलपत्र, बरगद, पिलखन, अशोक, जामुन शामिल हैं। अपनी इस मुहीम में उन्होंने अनेक नागरिकों को जोड़ा है। वर्ष 2017 में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलिथीन हटाओ, झोला अपनाओ आंदोलन भी चलाया था। डॉ. राजीव समय–समय पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गोष्ठियां, आंदोलन और जागरूकता रैली भी आयोजित करते हैं जिसमें वह आम जनमानस के साथ–साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी जोड़ते हैं। विशेष दिवसों यथा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव पर विशाल पौधारोपण किया जाता है। ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी मुहिम में गाजियाबाद में उनकी अहम भूमिका रही। 2017 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 25 करोड़ पौधारोपण के नागरिक आह्वाहन में उन्होंने गाजियाबाद में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वे 80000 से ज्यादा निःशुल्क तुलसी जी के पौधे वितरित कर चुके हैं। सामाजिक भाव को हृदय में लिए हुए वे 50 से अधिक निर्धन बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और साथ ही जरूरतमंदों के लिए रक्तदान भी करते हैं।

उन्होंने अपनी देह को भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान किया हुआ है। इसके साथ ही उन्हें आयुर्वेद का भी अच्छा ज्ञान है। वंचित वर्ग के 5 हजार से अधिक लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा कर उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व का पालन भी किया है।

ISSN No. 2581-3528

डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण

प्रहलाद सबनानी
सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

आज भारत, पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टि से एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभर रहा है। वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे वित्तीय एवं निवेश संस्थान भारत की आर्थिक प्रगति की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है और सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा संभवतः आगामी दो वर्षों में ही जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत आज अग्रसर है। इसी प्रकार, भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश भी बन चुका है एवं भारत का शेयर बाजार भी आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पूंजी बाजार बन चुका है। भारत ने वर्ष 1947 में जब राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। परंतु, वर्ष 1991 के बाद भारत में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में लागू किए सुधार कार्यक्रमों के बाद एवं विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद से भारत की आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है एवं भारत आज उक्त स्थिति में पहुंच गया है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने भी भारत द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के आर्थिक विकास का सपना देखा था एवं अर्थशास्त्र विषय पर उनकी अपनी अलग सोच थी। यह देश का दुर्भाग्य था कि भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्हें आर्थिक क्षेत्र में काम करने का मौका ही नहीं मिला। अन्यथा, आज भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत बन गई होती।

बाबा साहेब अम्बेडकर को हम केवल भारत के संविधान निर्माता के रूप में ही जानते हैं। परंतु, उन्होंने अपनी स्नातक एवं पी.एच.डी. की पढ़ाई विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र विषय में ही की थीं। बचपन से ही अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय रहा। अर्थशास्त्र के विभिन्न विषयों पर उनके उल्लेखनीय शोध कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। उक्त कारणों के चलते उनके सामाजिक कार्यों पर भी अर्थशास्त्र की छाप दिखाई देती थी। वे महिलाओं एवं दलितों को उद्यमी बनाने की बात करते थे तथा इस कार्य में तत्कालीन सरकार से इस संदर्भ में इन वर्गों की सहायता की अपील भी करते थे। उनका स्पष्ट मत था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनैतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। बाबा साहेब ने जिन विषयों पर अपने शोध कार्य किए थे उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं – भारतीय मुद्रा (रुपए) की बाजार मूल्य (विनिमय दर) की समस्या, महंगाई की समस्या, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या। उक्त विषयों पर आपने केवल शोध कार्य ही सम्पन्न नहीं किया बल्कि इनसे सम्बंधित कई समस्याओं के व्यावहारिक एवं तार्किक हल भी सुझाए थे। अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित प्राध्यापक श्री अंबीराजन ने मद्रास विश्वविद्यालय में अपने अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान में कहा था कि अम्बेडकर उन पहले भारतीयों में से एक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र में औपचारिक शिक्षा पाई और एक पेशेवर की तरह ज्ञान की इस शाखा का अध्ययन और उपयोग किया। भारतीय अर्थशास्त्र की परम्परा प्राचीन है। भारत में सदियों पहले 'अर्थशास्त्र', 'शुक्रनीति' और 'तिरुक्कुरल' जैसे ग्रंथ लिखे गए जबकि पश्चिम में अर्थशास्त्र का औपचारिक शिक्षण, 19वीं सदी के मध्य में प्रारम्भ हुआ। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि तत्कालीन सरकारों ने बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की अर्थ के क्षेत्र में गहन समझ एवं अध्ययन का लाभ नहीं उठाया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भी उस खंडकाल में ही कई देशों में तेजी से पनप रहे पूंजीवाद के दोषों को पहचान लिया था तथा पूंजीवाद का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने भारत में राष्ट्रीयत्व को प्राथमिकता देने का आह्वान किया था। बाद में, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारत को 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के आर्थिक पक्ष को उभारते हुए पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि सत्ता में रहने वाले दल की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज में पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक विभिन्न आर्थिक योजनाओं का लाभ पहुंचे,

अन्यथा उस दल को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाद के खंडकाल में श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने भी अर्थ को राष्ट्रीयत्व से जोड़ा था तथा इस संदर्भ में भारतीय नागरिकों में "स्व" के भाव को विकसित करने पर जोर दिया था। इसी प्रकार डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक दर्शन में भी लगभग यही दृष्टि दिखाई देती हैं। अम्बेडकर भी आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवाद के एकदम खिलाफ थे।

वर्ष 1923 में अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से डी.एस.सी. (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की थीं। डी.एस.सी. की थीसिस का विषय था "The Problem of the Rupee & Its Origin and its Solution" और, आपने उस समय पर रुपए के अवमूल्यन जैसी गम्भीर समस्या पर अपना शोध कार्य सम्पन्न किया था, जो उस खंडकाल में सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय का शोध कहा जाता है। आपने वर्ष 1923 में ही वित्त आयोग की चर्चा करते हुए सुझाव दिया था कि वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अवश्य आना चाहिए। साथ ही, लगभग इसी खंडकाल में आपने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का ब्लूप्रिंट तैयार करने में अपना योगदान दिया था। बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बाबा साहेब के इस योगदान को स्वीकार करते हुए अपनी स्थापना के 81 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में उनके नाम पर कुछ सिक्के जारी किए थे।

बाबा साहेब कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते थे और कृषि क्षेत्र के विकास के हिमायती थे। परंतु साथ ही, आप बड़े आकार के उद्योग के खिलाफ भी नहीं थे। आपका स्पष्ट मत था कि औद्योगिक क्रांति पर जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, देश की अधिकतम आबादी ग्रामों में निवास करती है एवं यह अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है और फिर उद्योग क्षेत्र के लिए कच्चा माल भी तो कृषि क्षेत्र ही प्रदान करता है। आधुनिक भारत की इमारत कृषि क्षेत्र के विकास पर ही खड़ी हो सकेगी। इन्हीं विचारों को दृष्टिगत रखकर आपने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी उपाय सुझाए थे। जैसे, कृषि योग्य भूमि के राष्ट्रीयकरण की आप वकालत करते थे। आप राज्य को यह दायित्व सौंपने की सोचते थे कि राज्य नागरिकों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए कि उससे नागरिकों की उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल हो जाए, इससे इन नागरिकों की आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा। साथ ही, निजी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और देश की सम्पदा का समाज में वितरण करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व का नियोजन भी होना चाहिए ताकि सामूहिक रूप से खेती को बढ़ावा दिया जा सके तथा इसी प्रकार उद्योग के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

"Small Holdings in India and their Remedies" नामक शोधग्रंथ डॉ. अम्बेडकर ने वर्ष 1918 में लिखा था। यह शोधग्रंथ, भारत में किसानों के सम्बंध में जमीनी यथार्थ की व्याख्या करने में उनके कौशल और आर्थिक समस्याओं के लिए व्यावहारिक नीतियों का सुझाव देने में इनकी प्रवीणता को दर्शाता है। इस शोधपत्र में की गई व्याख्या आज भी भारत में कृषि क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। आपका विचार था कि श्रम, पूंजी और संयत्र – तीनों भारत में कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। पूंजी वस्तु है और श्रमिक व्यक्ति। पूंजी का यदि कोई उपयोग न किया जाय तो उससे कोई आय नहीं होती परंतु उस पर कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। परंतु, श्रमिक, चाहे वह आय का अर्जन करे अथवा नहीं, उसे जीवित रहने के लिए स्वयं पर व्यय करना होता है। यदि वह यह खर्च उत्पादन से नहीं निकाल पाता, जैसा कि होना चाहिए, तो वह लूटपाट करने को मजबूर हो जाता है। इसी प्रकार भारत में छोटी जोतों की समस्या, दरअसल, उसकी सामाजिक अर्थव्यवस्था की समस्या है। अतः इस समस्या का स्थाई हल खोजना ही चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भारतीयता के अनुरूप लागू करना चाहते थे। यह उनकी सामाजिक आर्थिक संवेदना एवं सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर गहन वैचारिकी को प्रदर्शित करता है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में उस खंडकाल में दिए गए समस्त सुझाव आज की परिस्थितियों के बीच भी अति महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त माने जाते हैं। वर्तमान समय में हालांकि कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का हल निकालने में सफलता हासिल हुई है परंतु फिर भी डॉ. अम्बेडकर द्वारा उस खंडकाल में किए गए शोधकार्यों एवं सुझावों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जैसे, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, आय की असमानता, भारतीय रुपए का अवमूल्यन आदि के उन्मूलन पर विचार डॉ. अम्बेडकर द्वारा आर्थिक विषयों पर किए गए शोधों में देखे जा सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं अपने शोधों को भारतीय समाज के लिए व्यावहारिक स्तर पर लागू करने के सम्बंध में अपने सुझाव रखे थे। वे भारतीय समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भारतीयता के अनुरूप लागू करना चाहते थे। यह उनकी सामाजिक आर्थिक संवेदना एवं सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर गहन वैचारिकी को प्रदर्शित करता है। वे भारतीय आर्थिक व्यवस्था में भारतीय समाज में न्यायसंगत समानता, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, शून्य बेरोजगारी, नियंत्रित मुद्रा स्फीति, नागरिकों का आर्थिक शोषण नहीं होना एवं सामाजिक न्याय होना जैसी व्यवस्थाएं चाहते थे। यह व्यवस्थाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत के बहुत करीब हैं। ■

ISSN No. 2581-3528

लखपति दीदी
ग्रामीण सशक्तीकरण की उभरती लहर

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तृत मैदानों में, जहां संघर्ष की कहानियां अक्सर दृढ़ता से जुड़ी होती हैं, एक शांत क्रांति जन्म ले रही है। 'लखपति दीदी योजना', जिसने 11 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन गई है। यह पहल मात्र एक नीति नहीं है; यह भारतीय महिलाओं की अदम्य भावना और आर्थिक अवसर की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।

पिछले दशकों से, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक हाशिये पर रखा गया, उनके योगदान को कम आंका गया और उनकी महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। 'लखपति दीदी योजना' ने उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित कर इस कहानी को बदल दिया है। जो महिलाएँ कभी गरीबी की भूलभुलैया में भटकती थीं, आज वे मुनाफे और बैलेंस शीट की भाषा बोलती हैं। छोटे उद्यम चलाने से लेकर स्व–सहायता समूहों का संचालन करने तक, ये महिलाएं केवल आजीविका अर्जित नहीं कर रही हैं; वे विरासत को भी सहेज रही हैं।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गाँव की सावित्री देवी को लें। जो कभी गुज़ारे के लिए संघर्ष करती थीं, अब एक सफल जैविक खेती उद्यम चला रही हैं। वह गर्व से कहती हैं– 'अपने जीवन में पहली बार, मुझे सम्मान और आत्मनिर्भरता का अनुभव हो रहा है'। सावित्री जैसी कहानियाँ पूरे देश में गूँज रही हैं, जो परिवर्तन की जीवंत तस्वीर पेश करती हैं। फिर भी, जब हम इन उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करना ज़रूरी है जो प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। इन कार्यक्रमों को भारत के हर कोने में पहुँचाने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा, सतत् वित्त पोषण और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। डिजिटल विभाजन एक बड़ा अवरोधक बना हुआ है, क्योंकि कई महिलाओं के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुँच नहीं है, जो आधुनिक उद्यमिता के लिए आवश्यक उपकरण हैं। इसके अलावा, गहराई से जमे सामाजिक मानदंड अक्सर महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को दबा देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी सीमित हो जाती है।

नीति–निर्माताओं को इन अंतरालों को पाटने के लिए ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने, मार्गदर्शन कार्यक्रमों की व्यवस्था करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वजनिक–निजी साझेदारी के माध्यम से इस पहल के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है, जिसमें नवाचारपूर्ण समाधान और अतिरिक्त संसाधन जोड़े जा सकते हैं।

आगे बढ़ते हुए, हमें यह याद रखना होगा कि महिला सशक्तीकरण केवल न्याय का कार्य नहीं है; यह भविष्य में निवेश भी है। प्रत्येक 'लखपति दीदी' बदलाव की एक लहर का प्रतीक है, जिसमें प्रगति की सुनामी बनने की क्षमता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, 'यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।' आइए हम इस पीढ़ी को पोषित करें, क्योंकि उनके सशक्तीकरण में ही हमारे राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि निहित है।

–डॉ. परमवीर 'केसरी'

ISSN No. 2581-3528

मोहम्मद यूनुस और डीप स्टेट द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
ब्लॉगर एवं शिक्षाविद्

अगर आप हिंदू हैं और बांग्लादेश में रहते हैं, तो यह धरती पर नर्क की ताजा परिभाषा है। 1946 के नोआखली दंगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम हिंसा की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किए गए जघन्य अपराध दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए एक चेतावनी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तथाकथित मानवतावादी समूह या विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियाँ, विशेष रूप से कई बॉलीवुड सितारे, गाजा, सीरिया, लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध करने के लिए समय निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार के खिलाफ कभी विरोध करते नहीं दिखाई देते हैं। हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान का अत्याचार खत्म नहीं हो रहा। हालाँकि हमने 1921 का मोपला नरसंहार या 1990 का कश्मीर हिंदू नरसंहार नहीं देखा है, लेकिन हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रोजाना हिंदुओं के प्रति अपराधों को देख रहे हैं।

'मोहम्मद यूनुस और डीप स्टेट किस तरह हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं?'

- क्या तथाकथित कुछ मानवतावादियों, कई भारतीय राजनीतिक दलों और कुछ देशों के लिए हिंदू होना बेकार है जो स्वार्थ के लिए आतंकवादी संगठनों की सहायता करते हैं? नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहे अत्याचार बाकी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि कैसे एक आतंकवादी समर्थक और मानवता विरोधी व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहम्मद यूनुस शांतिदूत नहीं, बल्कि मानवता का कत्लेआम करने वाले हैं। क्या उनका नोबेल पुरस्कार रद्द नहीं कर दिया जाना चाहिए? कैसे अमेरिका का डीप स्टेट मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल बांग्लादेश और हिंदुओं को अपने स्वार्थ के लिए कमजोर करने के लिए कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इन डीप स्टेट तत्वों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करेंगे, जिनके अमेरिका या मानवता के लिए कोई अच्छे इरादे नहीं हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान के साथ यूनुस का संबंध आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और भारत विरोधी रुख को दर्शाता है। हिंदू संतों, पेशेवरों और व्यापारियों ने

ISSN No. 2581-3528

बांग्लादेश के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढावा देने के लिए कड़ी मेहनत की, कठिन समय के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमानों की सहायता की। हालाँकि, इन्हीं व्यक्तियों को क्रूरता से प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। हिंदुओं को वास्तव में इस पैटर्न और वैचारिक पहलुओं को समझना चाहिए; सरल शब्दों में कहें तो, 'शत्रुबोध' महत्वपूर्ण है।

हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कई राजनीतिक दलों की चुप्पी सभी हिंदुओं को एक स्पष्ट संदेश देती है– आप इन पार्टियों के लिए एक चुनावी उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं हैं, और यदि आप इन ताकतों के खिलाफ एकजुट नहीं होते हैं, तो आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। क्या ये पार्टियां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मौन समर्थन कर रही हैं? क्या हिंदुओं ने कभी बॉलीवुड हस्तियों को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की आलोचना करते सुना है? केवल कुछ ही ने ऐसा किया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र करोडो हिंदुओं का घर है। हालाँकि, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथियों की बर्बरताभरी हिंसा के बारे में चिंता या घृणा की आवाजें बहुत कम हैं। भारत में कुछ मीडिया आउटलेट इस तरह के अत्याचार पर चर्चा या इसे हाइलाइट कर रहे हैं। हिंदुओं, याद रखो कि, जबकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे हालाँकि, हमारा अस्तित्व पूरी तरह से एकता को मजबूत करने, किसी भी अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने, बचपन से आत्मरक्षा तकनीकों सहित सनातन संस्कृति को आत्मसात करने और धर्मांतरण से लड़ने पर निर्भर है...यह समय है कि संपूर्ण संत समुदाय, लाखों अनुयायियों के साथ मिलकर दुनिया को दिखाए कि हम हिंदुओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय या मानवता के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया को व्यापक भलाई के लिए हिंदुओं की शक्ति देखने दें। सनातन धर्म किसी पंथ का विरोधी नहीं है, बल्कि इसमें मानवता के लिए काम करके विश्व शांति को बढ़ावा देने की क्षमता है। सनातन धर्म का नुकसान मानवता और वैश्विक शांति का नुकसान है। इसलिए, दुनिया में हर कोई जो शांति चाहता है, उसे यूनुस सरकार और उसके लोगों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ किए गए अपराधों की कड़ी निंदा और कार्रवाई करनी चाहिए। यूनुस को यह समझने दें कि वह डीप स्टेट के समर्थन से मानव जाति के खिलाफ काम नहीं कर सकता।

संविधान के बारे में मूलभूत तथ्य यह है कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। तो क्या हम यह मान लें कि जाति के आधार पर हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास करने वाली राजनीतिक और डीप स्टेट वास्तव में डॉ. अंबेडकर के संविधान का विरोध करती हैं? वे हिंदुओं की आस्था प्रणाली को कमजोर क्यों करना चाहते हैं?

'दुनिया को हिंदुओं की स्थिति को किस तरह से देखना चाहिए?' -ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अपराधों की कड़ी निंदा की, साथ ही इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को जेल में डालने की निंदा करते हुए कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया नहीं जाना चाहिए। ब्लैकमैन ने ब्रिटेन की संसद में इस मामले को उठाया, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू आबादी की दुर्दशा को उजागर किया गया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उनके घरों और मंदिरों पर आगजनी और हमले सहित जानलेवा हिंसा की जाती है। बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश में एक हिंदू भिक्षु की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास को 'हिंदुओं पर सीधा हमला' बताया। दुनिया को यह जानने की जरूरत है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश दिखाते हैं कि जब हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते हैं तो क्या होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, हत्या, बलात्कार और देश से निष्कासन के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक आबादी में नाटकीय रूप से कमी आई है। क्या मानवीय संगठन, बौद्धिक वर्ग और राजनीतिक नेता अल्पसंख्यकों के लिए इस सबसे खराब स्थिति के प्रति अंधे हैं? भारत में इसके विपरीत हो रहा है, जहां बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यकों को जीवन के सभी पहलुओं में फलने–फूलने की इजाजत दे रहे हैं।

'भारत में संविधान सुरक्षित क्यों है?' -संविधान के बारे में मूलभूत तथ्य यह है कि डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। तो क्या हम यह मान लें कि जाति के आधार पर हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास करने वाली राजनीतिक और डीप स्टेट वास्तव में डॉ. अंबेडकर के संविधान का विरोध करती हैं? वे हिंदुओं की आस्था प्रणाली को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? हिंदुओं को व्यापक शोध और विश्लेषण करना चाहिए। वे निस्संदेह हिंदू एकता के महत्व और विभाजित हिंदू समुदाय के निहितार्थों के बारे में जानेंगे। ■

जन्मदिवस विशेष

सुब्रह्मण्य भारती

अपनी लेखनी से राष्ट्रीय जागरण करने वाले कवि एवं पत्रकार

सुब्रह्मण्य भारती भारत के दक्षिण प्रान्त तमिलनाडु में जन्में अद्वितीय प्रतिभा वाले स्वतंत्रता सेनानी, कवि, विचारक और लेखक थे। उनका जन्म 11 दिसम्बर 1882 को हुआ था। वे ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध थे उन्होंने तमिल भाषा में राष्ट्रीय जागरण से सम्बंधित काव्य रचनाएँ की थी। अद्‌भुत काव्य प्रतिभा के चलते इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारती एक जुझारू शिक्षक, देशप्रेमी और महान कवि के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। उनकी लेखनी से प्रेरित होकर दक्षिण भारतीय जनमानस स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ा था। वह कम उम्र में ही वाराणसी अपनी बुआ के पास आ गए थे, जहाँ उनका परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ था। चार साल के काशीवास में भारती ने संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। काशी में उनका सम्पर्क भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा निर्मित 'हरिश्चन्द्र मण्डल' से रहा।

तमिलनाडु लौटकर उन्होंने तमिल दैनिक 'स्वदेश मित्रम', तमिल साप्ताहिक 'इंडिया' और अंगेजी साप्ताहिक 'बाला भारतम' समाचार पत्रों में लेखन संपादन किया। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून का प्रकाशन शुरू किया था। इन पत्रों से न सिर्फ वह लोगों को अपेक्षित ज्ञान दिलाने में सफल रहे बल्कि उनकी रचनाओं का भी प्रकाशन हुआ। उसी समय उनकी रचनाधर्मिता चरम पर थी। उनकी रचनाओं में एक ओर जहाँ गूढ़ धार्मिक बातें होती थी वहीं रूस और फ्रांस की क्रांति तक की जानकारी होती थी। वह समाज के वंचित वर्ग और निर्धन लोगों की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहते थे। भारती पांडिचेरी में भी कई समाचार पत्रों के प्रकाशन संपादन से जुड़े रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में देशभक्ति की अलख जगाते रहे। पांडिचेरी में प्रवास के दिनों में वह गरम दल के कई प्रमुख नेताओं के संपर्क में रहे। वहाँ उन्होंने कर्मयोगी तथा आर्या के संपादन में श्री अरविन्द की सहायता भी की थी। एक क्रन्तिकारी के रूप में उन्होंने कोलकाता जाकर बम बनाना, पिस्तौल चलाना और गुरिल्ला युद्ध का भी प्रशिक्षण लिया। वे गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक के सम्पर्क में भी रहे। भारती ने नानासाहब पेशवा को मद्रास में छिपाकर रखा। स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आने के बाद उनकी जीवन के उत्तरार्ध के लेखन में हिन्दू राष्ट्रवाद का चिंतन दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हिन्दू राष्ट्रवाद का अंकुर उनके भीतर उनकी गुरु भगिनी निवेदिता और स्वामी जी की प्रेरणा के कारण उत्पन्न हुआ। भारती का प्रिय गान बंकिम चन्द्र का 'वन्दे मातरम्' था। 1905 में काशी में हुए 'कांग्रेस अधिवेशन' में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने यह गीत गाया। भारती भी उस अधिवेशन में थे। बस तभी से यह गान उनका जीवन का प्राण बन गया। मद्रास लौटकर भारती ने उस गीत का उसी लय में तमिल में पद्यानुवाद किया, जो आगे चलकर तमिलनाडु के घर-घर में गूँज उठा। 11 सितम्बर 1921 को इस महान आत्मा का देहावसान हो गया।

प्रेरणा विमर्श 2020 के अवसर पर केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक सिने विमर्श और भारतीय विरासत का विमोचन करते लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक अन्त्योदय की ओर का विमोचन करते सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ लेखिका अद्वैता काला जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक पत्रकारिता के अग्रदूत का विमोचन करते उत्तर प्रदेश के मा.राज्यपाल श्री राम नाईक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघचालक श्री सूर्यप्रकाश टोंक जी, माखनलाल चतुर्वेदी विवि. के पूर्व कुलपति श्री जगदीश उपासने जी व अन्य अतिथिगण